भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

ओडिशा में ड्रोन कॉरिडोर का विकास

4 श्री सुजीत कुमार:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का ओडिशा राज्य में चिकित्सा आपूर्ति वितरण, आपदा प्रतिक्रिया और कृषि सेवाओं में उपयोग के लिए समर्पित ड्रोन लेन बनाने का विचार है;
(ख) यदि हाँ, तो, कार्यान्वयन के लिए चयनित जिलों और क्षेत्रों सहित इन निर्दिष्ट मार्गों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उड़ान योजना या किसी अन्य माध्यम से, भुवनेश्वर के साथ-साथ राज्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करने के लिए कोई पहल की है;
(घ) ओडिशा के आदिवासी और तटीय क्षेत्रों में विमानन अवसंरचना विकास की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ङ) क्या चक्रवात और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में ड्रोन और छोटे विमानों के ज़रिए संभार तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): वर्तमान में, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): नागर विमानन मंत्रालय ने राजधानी भुवनेश्वर के अलावा भी उड़ीसा में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को संवर्धित करने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के अंतर्गत अनेक पहलें की हैं। चार हवाईअड्डों, झारसुगुडा, राउरकेला, उत्केला और जयपोर को आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत पहले ही विकसित और कार्यशील किया जा चुका है। भविष्य में आरसीएस परिचालनों को सहायता प्रदान करने के लिए तीन और हवाईपट्टियों नामतः रंगीलुंडा, अमरदा और रायरंगपुर (दंडाबोस) को विकास के लिए चिह्नित किया गया है।

उड़ान योजना के अंतर्गत रंगीलुंडा हवाईपट्टी पर राज्य सरकार दवारा वर्तमान में विकास कार्य किया जा रहा है तथा इसके 31 मार्च, 2026 तक पूरा होने की संभावना है। अमरदा और रायरंगपुर पर विकास कार्य योजना स्तर पर है चूंकि राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

ओडिशा में निम्नलिखित हवाईपट्टियां उड़ान दस्तावेज में असेवित हवाईपट्टियों की सूची में उपलब्ध हैं:
अंगुल, बारबिल, बीरासल, गुडारी, हीराकुंड, जयकपुर, लंजीगढ़, नुआपाड़ा, पदमपुर, रायसुअन, सुकिन्डा, थेरुबोली, तुशरा, मलकानगिरि, बारीपाडा और कोणार्क।

(ङ) नागर विमानन मंत्रालय ने चक्रवात और बाढ़-संभावित क्षेत्रों में ड्रोन और स्मॉल एयरक्राफ्ट लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया है।

******